Probe in Scrap Deal

586. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the Pioneer, dated 3rd September, 1997 under the heading "Centre may ask CBI to probe PSU Scrap deal";

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the case relating to the sale of scrap by the MSTC Ltd. to private firm has been referred to CBI; and

(d) the action taken by Government against the official concerned for awarding the sale to the private firm?

THE MINISTER OF STEEL AND THE MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) and (b) Yes, Sir, However, the press report is not wholly correct.

M/s. Sujana Steels Ltd., Hyderabad (and not Surana Steel as mentioned in the Press Report) had approached MSTC during early 1996 for purchase of 20,000 tonnes of shredded scrap from its Madras stockyard at the then ruling prices. The MSTC Board considered the request and decided (and not the then CMD, MSTC as alleged in the news report) to seel the stocks to the above firm under a tripartite agreement between M/s. MSTC Ltd., Sujana Steels Ltd. and SJK Steel Corporation Ltd. under the post-dated cheque facility scheme of the Company. Prior to this, MSTC had proposed to invest Rs. 15 crores in the equity of M/s. SJK Steel Corporation Ltd, of which M/s. Sujana Steels Ltd. was a joint co-promoter. According to the tripartite agreement Rs. 15 crores were to be adjusted against MSTC's equity participation in the above joint venture proposal subject to Government approval within a period of six months. In the absence of Government approval for the said joint venture proposals, the amount became due for payment but the post dated cheques furnished by M/s. Sujana Steels Ltd. bounced. In view of this, MSTC Ltd. has initiated legal proceedings against M/s. Sujana Steels Ltd. for recovery of the amount.

(c) The Ministry of Steel has not referred the matter relating to sale of scrap by MSTC through the private firm to CBI.

(d) Question does not arise in view of (a) & (b) above.

Failure of Sale Target of SAIL

587. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether the sale target of Steel Authority of India Limited has failed in the recent months; if so, the reasons of failure;

(b) whether the cheap import of steel is influencing the SAIL's market; and

(c) if so, the steps being taken to avoid this problem?

THE MINISTER OF STEEL AND THE MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) The total sales of pig iron and mild steel during the current financial year, upto October, 1997, have registered a growth over that of the corresponding period last year.

(b) and (c) Yes, Sir. Cheap import of steel is influencing the Indian steel producers' market including that of SAIL. Steps have been initiated for levying anti-dumping duty on such steel materials.

निजी क्षेत्र में इस्पात इकाइयों

588. **श्री चीमनभाई हरिभाई शुक्ला**:क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(**क**) विभित्र राज्यों में निजी क्षेत्र में स्थापित की गी इस्पात इकाइयों का उद्यतन ब्यौरा क्या है;

(**ख**) क्या उपर्युक्त किसी इकाई में कोई विदेशी निवेश किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस्पात की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्य कार्यवारी की गई है?

इस्पात मंत्री और खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) विभिश्र राज्यों में निजी क्षेत्र में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र और 177 विद्युत चाप भट्टी आधारित लुघु इस्पात संयंत्र स्थापित है जिनका ब्यौरा नीचे विवरण में दिया गया है। इन संयंत्रों के अतिरिक्त बहुत से प्रेरण भट्टी आधारित लघु इस्पात संयंत्र है जो अधिकांशत: **लघु क्षेत्र में है।**

(ख) और (ग) सरकार ने मैसर्स माटक लि. यु.के. द्वारा जमशेदपुर, बिहार में स्थित मौजूदा विद्युत चाप भट्टी आधारित संयंत्र मैसर्स उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैं 3.457 करोड़ रुपए के प्रतयक्ष विदेशी निवेश को अनुमोदित कर दिया है।

(घ) और (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता के बारे में सरकार को की विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हई है। तथापि, वह उल्लेखनीय हैं कि गुणवत्ता विशेष तौर से उदारीकरण के बाद के परिदृश्य में सदैव महत्वपुर्ण हैं और इस्पात का उत्पादन करने वाली कंप्नी को अपने आपको प्रति स्पर्धात्मक बनाने के लिए इस पहलु के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा।

विवरण

विभित्र राज्यों में निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	इकाइयों की कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	7
2.	आसाम	2
3.	बिहार	7
4.	चण्डीगढ़	1
5.	दिल्ली	2
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	7
8.	हरियाणा	12
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	जम्मू और कश्मीर	2
11.	कर्नाटक	11
12.	मध्य प्रदेश	15
13.	महाराष्ट्र	32
14.	उड़ीसा	1
15.	पाण्डिचेरी	3
16.	पंजाब	9
17.	राजस्थान	7
18.	तमिलनाडू	5
19.	उत्त प्रदेश	27
20.	पश्चिम बंगाल	23

वसंत विहार में पानी की कम आपुर्ति

589. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण**: क्या शहरी कार्य और रोजगार है कि सी.पी.डब्ल्यु.डी. कालोनी , वसंत विहार, नई दिल्ली के ब्लाक 71 तथा ब्लाक 72 के निवासियों को दुसरे ब्लाक के निवासियों की तुलना में पानी की बहुत कम मात्रा मिल रही है;

(ख) क्या , उक्त ब्लाकों में रहने वाले कर्मचारियों को प्रतिदिन सूबह 30 मिनट के लिए भी पानी उपलब्ध नही कराया जाता है;

(ग) क्या उक्त समस्या की ओर सी.पी.डब्ल्यु.डी. के किसी भी अधिकरारी द्वारा की ध्यान नहीं दिया गया है।

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) उक्त ब्लाकों के मिवासियों को पानी की उचित मात्रा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन-कौन से प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है; और (च) यदी हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भुतल परिवहन मंत्री तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन): (क) से (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सुचित किया है कि सी पी डब्ल्यु डी कालोनी के 71 एवं 72 ब्लाकों सहित वसन्त बिहार के सभी ब्लाकों को पानी का उचित वितरण किया जाता है।

(**ङ**)और (च) नगर निगम दिल्ली से इस कालोनी हैं जल आपुर्ति की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।